संख्या- 5/2025/I/983666/2025/02-5099/75/2025

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक: 04-06-2025

विषय : मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-538/2023 राजीब कालिता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय), उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.05.2025 ***(प्रति संलग्न)*** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 07.05.2025 का संदर्भ ग्रहण कराते हुए अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-538/2023 राजीब कालिता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में मा0 वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश पारित किये गये है:-

".....1. We resolve that the following members shall also be inducted to the existing District Monitoring Cell for the purpose mentioned above:-

- Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established)
- Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar palika (Municipality)

The Committee formed after the inclusion of above-mentioned members shall act as Coordination Committee at District Level....."

2- इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय), उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.05.2025 समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति के कार्यवृत्त में पारित निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

विजय कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक:04-06-2025

विषय : मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-538/2023 राजीब कालिता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय), उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.05.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 07.05.2025 का संदर्भ ग्रहण कराते हुए अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-538/2023 राजीब कालिता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में मा0 वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश पारित किये गये है:-

".....1. We resolve that the following members shall also be inducted to the existing District Monitoring Cell for the purpose mentioned above:-

- Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established)
- Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar palika (Municipality)

The Committee formed after the inclusion of above-mentioned members shall act as Coordination Committee at District Level....."

2- इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय), उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.05.2025 समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश

हुआ है कि कृपया मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में गठित समिति के कार्यवृत्त में पारित निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही/अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

Digitally signed by
VIJAY KUMAR
Date: 04-06-2025
19:16:48

(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)
संख्या-443 /सात-न्याय-2-2025-44 रिट/2023
लखनऊ:: दिनांक 20 मई, 2025

2256/PSA/2025
VS(V)

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
समस्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

कृपया महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-164/ इन्फ्रा.सेल (एचसी), दिनांक 07.05.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-538/2023 राजीब कालिता बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2025 के अनुपालन में मा0 वरिष्ठ न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की दिनांक 25.04.2025 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मा0 समिति द्वारा निम्नवत् निर्देश पारित किये गये है:-

23-05-2025
(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

".....1. We resolve that the following members shall also be inducted to the existing District Monitoring Cell for the purpose mentioned above:-

- **Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established)**
- **Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar palika (Municipality)**

The Committee formed after the inclusion of above-mentioned members shall act as Coordination Committee at District Level. ....."

1796/VSA/25
US(RPS)
27-05-2025

2. उक्त समिति की बैठक दिनांक 25.04.2025 का कार्यवृत्त एवं काम्प्रेहेन्सिव प्लान संलग्न है।

3. अत: अनुरोध है कि आपके विभाग के अन्तर्गत संचालित अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुए काम्प्रेहेन्सिव प्लान के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

20/05/25
(दिनेश सिंह)
विशेष सचिव।

US/505
27.5.25

Imp.
27.05.2025

संख्या- 497 /सात-न्याय-2/2025

Registrar General
High Court of Judicature
at Allahabad

D.O.No. 164/Infra.Cell(HC)
Dated: May 07 , 2025

Respected Sir,

Kindly refer to the meeting of the Hon'ble Committee constituted in compliance of order dated 15.01.2025 passed by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) no.538 of 2023 titled Rajeeb Kalita Vs. Union of India & Others, held on 25.04.2025.

In the aforesaid meeting the Hon'ble Committee has been pleased to pass the following directions (relevant excerpt):

" ..... 1. We resolve that the following members shall also be inducted to the existing District Monitoring Cell for the purpose mentioned above:-

- *Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established)*
- *Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar Palika (Municipality)*

The Committee formed after the inclusion of above-mentioned members shall act as Coordination Committee at District Level. ...."

Therefore, your goodself is requested to ensure the compliance of the directions of the Hon'ble Committee under an intimation to this end.

With regards,

Yours Sincerely

07/05/25

(Abhishek Srivastava, B.J.S)
Registrar (J)Infra-H.C
For Registrar General

Sri. Vinod Singh Rawat, B.J.S
Principal Secretary (Law) & L.R.
Government Of Uttar Pradesh
Lucknow, Uttar Pradesh

410/VS/05/25

सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 443 / dated-25/4/2025

Minutes of the meeting of Hon'ble the Committee constituted in compliance of order dated 15.01.2025 passed by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) no.538 of 2023 titled Rajeeb Kalita Vs. Union of India & Others, held on 25.04.2025.

Quorum:-
Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Gupta, Chairman
Sri. Manoj Kumar Singh, I.A.S, Chief Secretary, Govt. of U.P., Member
(via video-conferencing)
Sri.Deepak Kumar, I.A.S, Addl. Chief Secretary (Finance),Govt. of U.P., Member
(via video-conferencing)
Sri. Ajay Chauhan, I.A.S, Principal Secretary, PWD, Govt. of U.P., Member
(via video-conferencing)
Sri. Vinod Singh Rawat, H.J.S, Principal Secretary (Law) & L.R., Member
Sri. Vikrant Pandey, Secretary, High Court Bar Association, Allahabad, Member
(Did not attend the meeting)
Sri. Rohit Raghuwanshi, H.J.S, Registrar (J)(Infra.-District Courts), Member
Sri.Abhishek Srivastava, H.J.S, Registrar(Infra.-H.C), Member

Presenting Officer:
Sri.Abhishek Srivastava, H.J.S, Registrar(Infra.-H.C)

Pursuant to the order dated 15.01.2025 passed by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) no.538 of 2023 titled *Rajeeb Kalita Vs. Union of India & Others*, Hon'ble the Chief Justice of High Court, Allahabad, constituted a Committee vide order dated 31.01.2025 and subsequently reconstituted through orders dated 06.02.2025 & 27.02.2025.

The mandate of this Committee is to devise a comprehensive and inclusive plan for ensuring the establishment and accessibility of separate toilet facilities for males, females, persons with disabilities (PwD), and transgender persons at all Court premises and Tribunals across the State.

Agenda No.1:- To consider the Draft Comprehensive Plan for ensuring the construction and availability of separate toilet facilities for males, females, persons with disabilities (PwD) and transgender persons in all Court premises and Tribunals across the State of Uttar Pradesh.

&

Maintenance of the existing toilets as well as the toilets to be constructed under the plan.

Office has placed before us the draft comprehensive plan for the implementation of guidelines as enumerated in the order dated 15.01.2025 passed by the Hon'ble Apex Court.

Sd/-

(दिनेश सिंह)
संयुक्त सचिव एवं अपर सिविल परामर्शी
उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

We have perused the draft comprehensive plan. The draft plan is primarily fragmented into 03 parts. The part I is a set of directions issued to all the District Judges of District Court across the State.

Part I: Directions to the District Judges

1. Constitution of Health & Sanitization Committees at the District Court level.
2. Roles and responsibilities of the Committees.
3. Construction of new toilet facilities within District Court premises.
4. Maintenance of existing and new toilet facilities.
5. Staffing and engagement of outsourcing agencies for washroom upkeep.
6. Monitoring and evaluation mechanisms.
7. Public awareness campaigns emphasizing the significance of sanitation.

Part II:- Directions to the Registrar General of High Court and Senior Registrar of Lucknow Bench:- The part II of the draft plan is a set of directions for ensuring the availability, construction and maintenance of washrooms for different categories of person at Principal Bench and Lucknow Bench of High Court.

Part III:- Directions to the State Government

I. Allocation of adequate funds for the construction and maintenance of washrooms.
II. Formation of Coordination Committees at the District level.
III. Feasibility analysis for constructing washrooms near District Court premises.
IV. Mechanisms for expedited budget approval and sanctioning

During the deliberations, the Chief Secretary proposed that rather than establishing a new Coordination Committee at the District Level, the functions of the proposed committee should be entrusted to the existing Monitoring Cell in each District. This approach was deemed more practical and efficient, leveraging established mechanisms for effective coordination.

As per the draft plan, if the existing District Monitoring Cell is being opted, then the Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar Palika (Municipalilty) shall be inducted as a member of the existing Monitoring Cell for the purpose mentioned above.

The Principal Secretary (Law) & L.R., has submitted that the proposed Monitoring Cell would become more effective if the head of the Tribunals (situated within the District)/Family Court be also inducted as member of the Cell.

The Chief Secretary has expressed his agreement with both recommendations.

Sd/-

Additionally, while deliberating on the allocation of separate funds for the construction and maintenance of washrooms, the Additional Chief Secretary (Finance) informed that a corpus of ₹500 lacs has already been earmarked in the current budget. He assured that, upon submission of the detailed estimates for construction and maintenance of washrooms to the State Government, adequate funds would be provided to meet the requirements

Resolution:-

1. We resolve that following members shall also be inducted to the existing District Monitoring Cell for the purpose mentioned above:-

   - Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established).
   - Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar Palika (Municipality)

The Committee formed after the inclusion of above-mentioned members shall act as Coordination Committee at District Level.

2. The Office is directed to incorporate the change in the Part III of the draft comprehensive plan.

3. The office is directed to circulate the amended draft plan to the following authorities for necessary action:

i. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh
ii. The Additional Chief Secretary (Finance), Government of Uttar Pradesh
iii. The Principal Secretary, Public Works Department, Government of Uttar Pradesh
iv. The Principal Secretary (Law) & L.R.
v. All District Judges of the District Courts across the State
vi. The Secretary, High Court Bar Association, Allahabad
vii. The Registrar (Judicial) (Infrastructure - District Courts)

4. All the District Judges are directed to take immediate steps for the constitution of Health & Sanitization Committee at the District Level as per the Part I of draft plan and conduct a survey of the toilet facilities available within the Court premises and assess the existing toilet infrastructure as per the instructions enumerated in the draft plan.

5. All the District Judges are directed to submit the survey report to the High Court within one week.

6. The State Government is directed to submit the compliance report of directions enumerated in the Part III of the draft plan within one week.

Sd/-

7. The Registrar General of High Court & the Senior Registrar, Lucknow Bench, Lucknow is directed to constitute the Health & Sanitization Committee at Principal Bench & Lucknow Bench of High Court as per the Part II of the draft plan within one week.

8. The Health & Sanitization Committee at Principal Bench & Lucknow Bench of High Court shall conduct a survey as per the Part II of draft plan within week.

9. The draft comprehensive plan shall be the part of these minutes.

Let these minutes be placed before Hon'ble the Chief Justice for his Lordship's kind perusal and orders.

Sd/-

Justice Manoj Kumar Gupta
(Chairman)
Senior Judge, High Court of Judicature at Allahabad (Principal Bench)

Sri. Deepak Kumar, I.A.S
(Member)
Addl. Chief Secretary (Finance)

Sri. Manoj Kumar Singh, I.A.S
(Member)
Chief Secretary

Sri. Vinod Singh Rawat, H.J.S
(Member)
Principal Secretary (Law) & L.R

for Prakash Bindu, Secretary PWD

Sri. Ajay Chauhan, I.A.S
(Member)
Principal Secretary, PWD

Sri.Abhishek Srivastava, H.J.S
(Member)
Registrar (J)(Infra.-High Court)

Sri. Rohit Raghuwanshi, H.J.S
(Member)
Registrar(J)(Infra.-District Courts)

Sd/-

Arun Bhansali
CHIEF JUSTICE

COMPREHENSIVE PLAN

(TO ENSURE THE CONSTRUCTION & AVAILABILITY OF SEPARATE TOILETS FACILITIES FOR MALES, FEMALES, PwD AND TRANSGENDERS)

PART-I

Draft Comprehensive plan for District Judiciary to ensure the construction and availability of separate toilets facilities for males, females, PwD and transgenders.

Directions to all the District Judges regarding above-captioned subject matter:-

1. **Constitution of Health & Sanitization Committee at the District Court level:-** All the members of District Court Infrastructure Sub-Committee shall be the members of the Committee. Additionally, if no female Judicial Officer is included in the Sub-Committee then a female Civil Judge (Senior Division), an Executive Engineer, UPPWD and one officer of Municipal Corporation, not below the rank of Executive Engineer, shall be the member of the Committee. The Chairman of District Court Infrastructure Sub-Committee shall be the Chairman of Health & Sanitization Committee at the District Court level.

The District Judge shall also induct a Judicial Officer of PwD/Transgender category as member of the Committee if the Judicial Officer of said category is posted in the District Court.

2. The Health & Sanitization Committee shall conduct a survey of the toilet facilities available within Court Premises and assess the existing toilet infrastructure on following points:-

i. The per-day average footfall in the Court premises.

ii. Total number of toilets available for male, female, persons with disabilities (PwD) and transgender persons within the Court premises.

iii. Total number of new toilets required to be constructed or converting the existing toilet for above-mentioned categories as per the National Building Code (NBC) or any other building code approved by the Centre/State Government.

iv. To assess the need of alternate toilet facilities like mobile toilets and bio-toilets during the period of construction of new toilets or renovation of existing toilets or where there is a space crunch within the Court's premises.

v. To check whether the clear signage and indications are affixed outside the toilet facilities specifically for female, transgender persons and persons with disability.

vi. To check the availability of amenities like water, electricity, operationability of flushes, provision of hand soap, napkins, toilet paper and up to date plumbing system in the toilet facilities meant for female, transgender persons and persons with disability.

sdt

vii. To ensure that the ramps are installed and that washrooms are designed in a manner to accommodate persons with disabilities (PwD).

viii. To explore the possibility to build washrooms at underutilized spaces in Heritage Court buildings and to provide modular solutions for the old plumbing systems as well as to modernize the existing sanitation facilities.

3. Special Instructions regarding construction of new toilets in the District Court premises.

i. <u>Female toilets</u>

- Installation of sanitary pad dispensers and disposal machine
- Installation of liquid soap dispensers
- Provide hooks and shelves for storing belongings during use, and for hanging clothes or drying reusable menstrual products
- Installation of secure locks on toilet doors to ensure privacy
- Clear Signage: Use clear and visible signage to indicate the location of the washroom and its features
- Adequate Lighting: Ensure adequate lighting both inside and outside the washroom for safety
- Provide separate rooms interconnected with the female washrooms to cater to nursing mothers' for feeding infants and for changing diapers.

ii. <u>Persons with disability (PwD) toilet</u>

- Grab Bars: Strategically placed horizontal and vertical grab bars provide support for sitting, standing, and maneuvering.
- Spacious Design: Extra space allows for easy wheelchair movement, with a considerable turning radius.
- Accessible Fixtures: Sinks, mirrors, and soap dispensers are mounted at lower heights for easy reach.
- Non-Slip Flooring: Ensures safety by reducing the risk of slips and falls.
- Door Features: Outward-opening or sliding doors with easy-to-use handles enhance accessibility.
- Emergency Assistance: Some facilities include alarm systems or call buttons for emergencies.

iii. <u>Transgender toilet</u>

- Unisex Design: These toilets are often gender-neutral,

  unlike traditional men's restroom with urinals, gender neutral toilets typically have only toilet stalls, ensuring privacy for all users.

Sd/-

- Privacy: Enhanced privacy measures, such as full-length doors and enclosed stalls, ensure a safe and respectful environment. Toilets are installed in enclosed cubicles with floor-to-ceiling walls to ensure visual privacy for all users.
- Accessibility: These washrooms are designed to be accessible for all users, including those with disabilities, with features like wider stalls, grab bars, and accessible sinks.
- No Gendered Language : Avoid any language or symbols that could be perceived as gendered, ensuring a welcoming space for all
- Gender-Neutral Signage: Washrooms are clearly labeled as "All-Gender" or "Gender-Neutral" to avoid confusion and ensure that all users feel welcome.
- Safety Measures: Emergency call buttons or alarms may be installed for added security.

iv. <u>Child safe washrooms in Family Court complexes</u>

- The Family Court complexes shall have child safe washrooms with trained staff equipped to provide children with a safe and hygienic space.
- Non-slip flooring:Ensures children can move around safely, especially when wet.
- Rounded edges: Reduces the risk of injury from sharp corners.
- Adequate lighting: Allows children to see clearly and navigate the restroom safely.
- Easy-to-use locking systems: Cubicles should have simple locks that children can easily operate.
- Child-sized toilets: Some restrooms may have smaller toilets designed for children's needs.
- Step stools: Make sinks accessible for younger children.
- Kid-friendly decor: Bright colors, fun graphics, and themes can make the restroom less intimidating for children.
- Easy-to-understand signage: Clear and simple signage can help children navigate the restroom.
- Easy hand-washing: Sinks should be easily accessible for children, with soap and hand sanitizer readily available.
- Disposable toilet seat covers

Sd/-

4. Special instructions regarding maintenance of toilets situated within Court premises:-

Cleaning and Sanitation

- Regular Cleaning Schedule: Implement a strict cleaning schedule, with daily general cleaning and more thorough cleaning on a weekly, fortnightly, or monthly basis, depending on traffic and materials.
- Disinfecting Surfaces:Disinfect frequently touched surfaces, including toilet seats, flush handles, faucet handles, and door handles, using appropriate disinfectants.
- Floor Cleaning: Ensure Sweeping or mopping of floor on regular basis using a disinfectant solution and upkeeping dry bathroom floors.
- Waste Disposal: Ensure proper disposal of used paper napkins and other waste in foot-operated dustbins with lids

Maintenance and Repairs

- Leak Detection and Repair: Regularly check for leaks and drips and address them promptly.
- Fixture Inspection: Inspect all fixtures, including flush handles, flappers, and water levels, and replace parts as needed.
- Electrical Safety: Regularly check the condition of electrical switchboards and other electrical fixtures.
- Spare Parts: Keep a supply of spare parts and consumables, such as toilet paper, soap, and cleaning supplies, readily available.

Hygiene and Safety

- Ensure that there are working and stocked sanitary pad dispensers in women, PwD, and transgender washrooms.
- Personal Protective Equipment (PPE): Caretakers should wear masks and gloves while cleaning and disinfecting toilets.
- Cleaning Equipment:Disinfect cleaning equipment after use and store it properly
- Cross-Contamination Prevention:Dispose of cleaning materials (mops, wiping cloths) in appropriate bags after use to prevent cross-contamination
- Foot Operated Dustbins: Replace all the existing dustbins with foot operated dustbin with proper lid

SDF

5. Staffing and outsourcing professional agencies for maintenance/cleanliness of washroom

Staff for maintenance of washroom

- All the District Court/Civil Court/Tribunal/Family Court shall nominate or appoint a Nodal Officer, preferably the Officer In-charge (Nazarat), to monitor the maintenance, address the complaints and communicate with the Health & Sanitization Committee.
- The Committee shall address the complaints and give standing instructions in writing regarding maintenance and working of the said toilets and shall fix responsibilities.
- Caretaker/Supervisor:- There shall be a post of Caretaker/Supervisor for every District Court to oversee the entire toilet facility, ensuring cleanliness, functionality and safety.
- The Caretaker/Supervisor shall supervise the cleaning staff, monitor the facility's condition and address any issues, ensure proper waste disposal and hygiene practices, maintain records of cleaning schedules and maintenance activities, handle user inquiries and complaints.
- The Nodal Officer along with Caretaker/Supervisor shall undertake periodic inspection of the functionality of washrooms.
- The Committee shall frame a complaint /redressal system for speedy reporting of defective washrooms and instant repair of the same.
- The Nodal Officer shall place the inspection report, specific compliance reports and other relevant data before the Committee on monthly basis.
- The Health & Sanitization Committee shall conduct a survey along with Nodal Officer to assess the requirement of cleaning staff and accordingly prepare a proposal along with budgetary demands for hiring cleaning staff on permanent and contractual basis.
- Training:- Provide training for staff responsible for managing and maintaining public toilets including sanitation workers and caretakers.

Outsourcing professional agencies

- For employing modern cleaning methods and machinery to ensure better hygiene and usability, the Health & Sanitization Committee shall assess the specific need of outsourcing professional agencies on contract basis and accordingly prepare

Sd/-

a proposal along with budgetary demands.

6. **Monitoring and evaluation**

- Implement robust monitoring and evaluation system to assess the performance of public toilets.
- Identify areas for improvement and ensure compliance

7. **Awareness**

- Promote public awareness about the importance of sanitation and recognize the right to sanitation as a fundamental human right.

Sd/-

PART-II

Draft Comprehensive plan for Principal Bench & Lucknow Bench of High Court to ensure the construction and availability of separate toilets facilities for males, females, PwD and transgenders.

1. Constitution of Health & Sanitization Committee for Principal Bench & Lucknow Bench of High Court:-

There shall be a Health & Sanitization Committee for Principal Bench & Lucknow Bench of High Court.

The Health & Sanitization Committee of Principal Bench of High Court shall comprise following members:-

- Registrar(Protocol/Nazarat)
- Chief Court Officer (Nazarat)
- Executive Engineer, Construction Division-I & III, Prayagraj
- Executive Engineer, Municipal Corporation, Prayagraj

The Health & Sanitization Committee of Lucknow Bench of High Court shall comprise following members:-

- Registrar(Nazarat)
- Court Officer(Nazarat)
- Executive Engineer, Construction Division, Lucknow
- Executive Engineer, Municipal Corporation, Lucknow

The Registrar (Protocol/Nazarat) and Registrar (Nazarat) shall be the Chairman of Health & Sanitization Committee of Principal Bench & Lucknow Bench of High Court respectively.

2. The Health & Sanitization Committee of Principal Bench & Lucknow Bench of High Court shall conduct a survey of the toilet facilities available within Court Premises and assess the existing toilet infrastructure on following points:-

i. The per-day average footfall in the Court premises.

ii. Total number of toilets available for male, female, persons with disabilities (PwD) and transgender persons within the Court premises.

iii. Total number of new toilets required to be constructed or converting the existing toilet for above-mentioned categories as per the National Building Code (NBC) or any other building code approved by the Centre/State Government.

iv. To assess the need of alternate toilet facilities like mobile toilets and bio-toilets.

v. To check whether the clear signage and indications are affixed outside the toilet facilities specifically for female, transgender persons and persons with disability.

Sd/-

vi. To check the availability of amenities like water, electricity, operationability of flushes, provision of hand soap, napkins, toilet paper and up to date plumbing system in the toilet facilities meant for female, transgender persons and persons with disability.

vii. To ensure that the ramps are installed and that washrooms are designed in a manner to accommodate persons with disabilities (PwD).

viii. To explore the possibility to build washrooms at underutilized spaces in Heritage Court buildings and to provide modular solutions for the old plumbing systems as well as to modernize the existing sanitation facilities

3. Special Instructions regarding construction of new toilets in the High Court premises.

i. <u>Female toilets</u>

- Installation of sanitary pad dispensers and disposal machine
- Installation of liquid soap dispensers
- Provide hooks and shelves for storing belongings during use, and for hanging clothes or drying reusable menstrual products
- Installation of secure locks on toilet doors to ensure privacy
- Clear Signage: Use clear and visible signage to indicate the location of the washroom and its features
- Adequate Lighting: Ensure adequate lighting both inside and outside the washroom for safety
- Provide separate rooms interconnected with the female washrooms to cater to nursing mothers' for feeding infants and for changing diapers.

ii. <u>Persons with disability (PwD) toilet</u>

- Grab Bars: Strategically placed horizontal and vertical grab bars provide support for sitting, standing, and maneuvering.
- Spacious Design: Extra space allows for easy wheelchair movement, with a considerable turning radius.
- Accessible Fixtures: Sinks, mirrors, and soap dispensers are mounted at lower heights for easy reach.
- Non-Slip Flooring: Ensures safety by reducing the risk of slips and falls.
- Door Features: Outward-opening or sliding doors with easy-to-use handles enhance accessibility.
- Emergency Assistance: Some facilities include alarm systems or call buttons for emergencies

Sd/-

iii. **Transgender toilet**

- Unisex Design: These toilets are often gender-neutral, unlike traditional men's restroom with urinals, gender neutral toilets typically have only toilet stalls, ensuring privacy for all users.
- Privacy: Enhanced privacy measures, such as full-length doors and enclosed stalls, ensure a safe and respectful environment. Toilets are installed in enclosed cubicles with floor-to-ceiling walls to ensure visual privacy for all users.
- Accessibility: These washrooms are designed to be accessible for all users, including those with disabilities, with features like wider stalls, grab bars, and accessible sinks.
- No Gendered Language : Avoid any language or symbols that could be perceived as gendered, ensuring a welcoming space for all
- Gender-Neutral Signage: Washrooms are clearly labeled as "All-Gender" or "Gender-Neutral" to avoid confusion and ensure that all users feel welcome.
- Safety Measures: Emergency call buttons or alarms may be installed for added security.

iv. **Child safe washrooms for Mediation Centre**

- The Mediation Centre shall have child safe washrooms with trained staff equipped to provide children with a safe and hygienic space.
- Non-slip flooring: Ensures children can move around safely, especially when wet.
- Rounded edges: Reduces the risk of injury from sharp corners.
- Adequate lighting: Allows children to see clearly and navigate the restroom safely.
- Easy-to-use locking systems: Cubicles should have simple locks that children can easily operate.
- Child-sized toilets: Some restrooms may have smaller toilets designed for children's needs.
- Step stools: Make sinks accessible for younger children.
- Kid-friendly decor: Bright colors, fun graphics, and themes can make the restroom less intimidating for children.
- Easy-to-understand signage: Clear and simple signage can help children navigate the restroom.
- Easy hand-washing: Sinks should be easily accessible for children, with soap and hand sanitizer readily available.

sdl-

- Disposable toilet seat covers

4. Special instructions regarding maintenance of toilets situated within High Court premises:-

Cleaning and Sanitation

- Regular Cleaning Schedule: Implement a strict cleaning schedule, with daily general cleaning and more thorough cleaning on a weekly, fortnightly, or monthly basis, depending on traffic and materials.
- Disinfecting Surfaces:Disinfect frequently touched surfaces, including toilet seats, flush handles, faucet handles, and door handles, using appropriate disinfectants.
- Floor Cleaning: Ensure Sweeping or mopping of floor on regular basis using a disinfectant solution and upkeeping dry bathroom floors.
- Waste Disposal: Ensure proper disposal of used paper napkins and other waste in foot-operated dustbins with lids

Maintenance and Repairs

- Leak Detection and Repair: Regularly check for leaks and drips and address them promptly.
- Fixture Inspection: Inspect all fixtures, including flush handles, flappers, and water levels, and replace parts as needed.
- Electrical Safety: Regularly check the condition of electrical switchboards and other electrical fixtures.
- Spare Parts: Keep a supply of spare parts and consumables, such as toilet paper, soap, and cleaning supplies, readily available.

Hygiene and Safety

- Ensure that there are working and stocked sanitary pad dispensers in women, PwD, and transgender washrooms.
- Personal Protective Equipment (PPE): Caretakers should wear masks and gloves while cleaning and disinfecting toilets.
- Cleaning Equipment: Disinfect cleaning equipment after use and store it properly.
- Cross-Contamination Prevention: Dispose of cleaning materials (mops, wiping cloths) in appropriate bags after use to prevent cross-contamination.
- Foot Operated Dustbins: Replace all the existing dustbins with foot operated dustbin with proper lid.

5. Staffing and outsourcing professional agencies for maintenance of washrooms

Staff for maintenance of washroom

- Chief Court Officer (Nazarat) & Court Officer (Nazarat) shall be the Nodal Officer of Principal Bench & Lucknow Bench of High Court respectively, to monitor the maintenance, address the complaints and communicate with the Health & Sanitization Committee.
- The Committee shall address the complaints and give standing instructions in writing regarding maintenance and working of the said toilets and shall fix responsibilities.
- Caretaker/Supervisor:- Chief Court Officer (Nazarat) & Court Officer (Nazarat) of Principal Bench & Lucknow Bench of High Court respectively shall nominate a Caretaker/Supervisor to oversee the entire toilet facility, ensuring cleanliness, functionality and safety.
- The Caretaker/Supervisor shall supervise the cleaning staff, monitor the facility's condition and address any issues, ensure proper waste disposal and hygiene practices, maintain records of cleaning schedules and maintenance activities, handle user inquiries and complaints.
- The Nodal Officer along with Caretaker/Supervisor shall undertake periodic inspection of the functionality of washrooms.
- The Committee shall frame a complaint /redressal system for speedy reporting of defective washrooms and instant repair of the same.
- The Nodal Officer shall place the inspection report, specific compliance reports and other relevant data before the Committee on monthly basis.
- The Health & Sanitization Committee shall conduct a survey along with Nodal Officer to assess the requirement of cleaning staff and accordingly prepare a proposal along with budgetary demands for hiring cleaning staff on permanent and contractual basis.

Outsourcing professional agencies

- For employing modern cleaning methods and machinery to ensure better hygiene and usability, the Health & Sanitization Committee shall assess the specific need of outsourcing professional agencies on contract basis and accordingly prepare a proposal along with budgetary demands.

Sd/-

PART-III

Directions to State Government in order to comply with the order passed by Hon'ble the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) no.538 of 2023, titled Rajeeb Kalita Vs Union of India & Others

1. **Allocation of separate fund for Construction of Washrooms and its Maintenance**

The State Government shall allocate sufficient funds for construction, maintenance and cleanliness of the toilet facilities within the Court premises (including Tribunals) across the State of Uttar Pradesh, which shall be periodically reviewed in consultation with the Hon'ble Committee of High Court.

2. **Co-ordination Committee at District Level**

The State Government shall take necessary steps to include the following members to the existing District Monitoring Cell which shall act as Coordination Committee at District Level:-

- Head of the Tribunals/Family Court (District where Tribunals/Family Courts are established)
- Nagar Aayukt (Municipal Commissioner) or the head executive officer of Nagar Palika (Municipallity)

The Coordination Committee shall coordinate with the Health & Sanitization Committee of District Court for the implementation of the directions issued under the draft comprehensive plan.

3. The Coordination Committee shall also endeavor to explore the possibility of construction of all category friendly public toilets nearby the premises of District Courts to cater the influx of litigants visiting the District Court.

The toilets that may be constructed nearby the premises of District Courts can be sustained by:-

(i) Exploring public-private partnerships to leverage private sector expertise and resources for the construction and management of public toilets.

(ii) Develop sustainable funding models including user fees, grants, government funding etc.

4. The State Government shall devise a mechanism which ensures the expeditious examination of preliminary estimate, sanctioning of budget and release of fund for the purpose mentioned above.

sd/